IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 3 | सांचौर, रविवार, 1 फरवरी 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

एनसीडी पर 8.5 लाख से ज्यादा को-आपरेटिव पंजीकृत

नई दिल्लीः राष्ट्रीय को-आपरेटिव डाटा (एनसीडी) पर अब तक 8.5 लाख से ज्यादा कोआपरेटिव पंजीकृत हो चुकी है और इसमें से करीब 6.6 लाख कोआपरेटिव संचालित हो रहे हैं। आधिकारिक डाटा के अनुसार, यह कोआपरेटिव ग्रामीण भारत के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं और 30 सेक्टरों में लगभग 32 करोड़ सदस्यों को सेवा देते हैं। यह संस्थाएं दूध उत्पादकों, कारीगरों, मछुआरों, व्यापारियों और श्रमिकों को बाजारों से जोड़ती हैं।

अनुशासनात्मक नोटिस की तामीली अब होगी डिजिटल

जयपुर । सहकारिता विभाग ने कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों के उपयोग हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत नियम 16 व 17 के नोटिसों की तामीली भौतिक रूप के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी की जा सकेगी। इसके लिए आईएचआरएमएस पोर्टल पर 'ई-इन्क्वायरी मॉड्यूल' विकसित किया गया है। कार्मिकों को नोटिस अब एसएसओ डैशबोर्ड, राजकीय ईमेल, व्यक्तिगत ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भौतिक रूप से तामीली न होने पर इन डिजिटल माध्यमों से दी गई सूचना को ही पर्याप्त मानकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

कृषि उपज मण्डी, मेड़ता सिटी में बनेंगे नवीन किसान पथ

जयपुर, । नागौर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, मेड़ता सिटी के अंतर्गत 5 नवीन सम्पर्क सड़कों (किसान पथ) के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 करोड़ 60 लाख रूपये से अधिक की राशि स्वीकृति की है। इन संपर्क सड़कों के निर्माण से ग्रामीणों व किसानों के आवागमन एवं कृषि जिन्सों को मण्डी तक लाने में सुविधा होगी।

कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर देय ब्याज के तौर पर करीब 765 करोड़ की राशि बकाया : एक साल पूर्व पीडी खाते में जमा हुए थे 200 करोड़

खुली 'कुंभकर्णी' नींद : केंद्रीय सहकारी बैंकों की 200 करोड़ की राशि को लेकर फिर हुआ पत्राचार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर 8 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा के तहत एक साल पूर्व 200 करोड़ की राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) के पर्सनल डिपॉजिट (पीडी) अकाउंट में सरकार ने जमा की थी अब इस राशि को लेकर एक बार फिर पत्राचार का दौर शुरू हुआ है दरअसल राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (एसएलडीबी) को 95 लाख एवं 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) को 199 करोड़ 55 लाख की राशि का भुगतान करने के क्रम में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) प्रबंध निदेशक ने हाल ही में सहकारिता विभाग पंजीयक (Rcs) कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) को एक पत्र भेजा हैं । जो 'सहकार से समृद्धि' लाने वाले सहकारिता विभाग में फाइलों की सुस्त चाल को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है । हैरानी की बात यह है कि जिस 200 करोड़ की राशि को सहकारिता विभाग ने 21 मार्च 2025 को एक आदेश जारी कर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) के पीडी खाते में हस्तांतरित किया था । वह भारी-भरकम राशि पिछले करीब एक साल से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के पीडी खाते में 'आराम' फरमा रही थी। जबकि राज्य सरकार की कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर ब्याज देने की घोषणा के तहत अब तक 765 करोड़ की भारी-भरकम राशि बकाया बताई जा रही है। इस राशि के प्रावधान के चलते प्रदेश के अधिकांश केंद्रीय सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हानि में चले गए हैं । अब 765 करोड़ की राशि के आवंटन को लेकर केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी 9 फरवरी को जयपुर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए हैं ।

एसएलडीबी को 95 लाख एवं 29 सीसीबी को 199 करोड़ 55 लाख की राशि का होना हैं भुगतान

765 करोड़ की राशि के आवंटन को लेकर केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी 9 फरवरी को जयपुर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए

संगठन ने आंदोलन की रणनीति तैयार की

-आगामी 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट से पहले संगठन ने आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इसके तहत आगामी 4 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में स्थित सीसीबी के प्रधान कार्यालयों पर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात, 9 फरवरी को राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय विशाल रैली और प्रदर्शन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश की केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्मिक शामिल होंगे।

-सूरजभानसिंह आमेरा
सहकार नेता

एक्सपर्ट व्यू : संचित हानि में केंद्रीय सहकारी बैंक, फिर भी कार्यशैली में 'नवाबी' ठाट

विडंबना देखिए कि राजस्थान के अधिकतर केंद्रीय सहकारी बैंक वर्तमान में संचित हानि और एनपीए की मार झेल रहे हैं। बैंक अक्सर संसाधनों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन जब सरकार से पैसा मिल जाता है, तो उसे जरूरतमंद तक पहुंचाने में साल भर लगा दिया जाता है। इस देरी की वजह से न केवल केंद्रीय सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ती है, बल्कि पूरी सहकारी व्यवस्था की साख पर भी बट्टा लगता है। ताजा आदेश के मुताबिक, अब बाड़मेर को 21.26 करोड़ और जोधपुर को 13.46 करोड़ जैसे बड़े भुगतान होने हैं। अगर यही मुस्तैदी साल भर पहले दिखाई गई होती, तो शायद इन बैंकों की वित्तीय स्थिति आज कुछ और होती। पर साहब, यह सहकारी व्यवस्था है, यहाँ काम 'फुर्ती' से नहीं, 'फुरसत' से होता है!

सूची लंबी है

पीडी खाते में पड़ी 200 करोड़ की राशि की सूची लंबी है, अजमेर से लेकर उदयपुर तक और बाड़मेर से लेकर झालावाड़ तक। बाड़मेर के लिए 21.26 करोड़ और जोधपुर के लिए 13.46 करोड़ जैसी बड़ी राशियां अटकी हुई हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों को उम्मीद थी कि कर्जमाफी का ब्याज उन्हें राहत देगा, लेकिन यहाँ तो फाइल खुद कर्जदार नजर आती है वक्त की और लालफीताशाही की । डिजिटल इंडिया के दौर में जब पलक झपकते ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ राजस्थान का सहकारिता विभाग एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक पैसा पहुँचाने में साल-दर-साल का समय ले रहा है। खैर, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत भी यहाँ फीकी है, क्योंकि यहाँ तो 'देर' ही सिस्टम की पहचान बन चुकी है। अब देखना यह है कि 19 जनवरी 2026 को निकला यह आदेश वास्तव में कब बैंकों के खातों में 'क्रेडिट' का मैसेज बनकर टपकेगा, या फिर अगली किसी तारीख का इंतजार करेगा।

सहकारी समितियों में कर्मचारियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया एक बार फिर विवादों के घेरे में

बाड़मेर जिले की सहकारी समितियों में नियुक्तियों और स्थाईकरण पर उठे सवाल, तलब की तथ्यात्मक रिपोर्ट

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कर्मचारियों के स्थाईकरण के लिए वर्ष 2022 में सहकारिता विभाग द्वारा चलाई गई स्क्रीनिंग प्रक्रिया एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इस बार सीमावर्ती बाड़मेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इस प्रक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर हुए कथित फर्जीवाड़े की शिकायत विधानसभा तक पहुँचने के बाद सहकारिता विभाग पूरी तरह हरकत में आ गया है। सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर को इस मामले में गहन जांच कर 'तथ्यात्मक रिपोर्ट' पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर ने जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक को एक पत्र जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है । जिसके बाद विभागीय निर्देशों की अनुपालना में जालोर सीसीबी प्रबंध निदेशक ने बाड़मेर सीसीबी प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा हैं। इसमें मुख्य रूप से वर्ष 2022 में स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए नियमित किए गए कार्मिकों की सूची, उनके वेतन भुगतान का विवरण और स्क्रीनिंग से संबंधित पत्रावलियां मांगी गई हैं। साथ ही, सभी पत्रावलियों को कार्यालय में सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप

- **फर्जी नियुक्तियां :** नियमों को ताक पर रखकर अपात्र लोगों को भर्ती करना।
- **ऑडिट में हेराफेरी :** वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट में बदलाव कर गड़बड़ियों को छिपाना।
- **वित्तीय भ्रष्टाचार :** सरकारी धन और सहकारी तंत्र को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाना।
- **फर्जी ऋण माफी :** अपात्र व्यक्तियों को नियम विरुद्ध ऋण माफी का लाभ देना।

विधानसभा 'अति आवश्यक' श्रेणी में जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) ने इसे 'विधानसभा अति आवश्यक' श्रेणी में रखा है। साथ ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर और बाड़मेर सीसीबी प्रबंध निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शिकायत में वर्णित तथ्यों का सूक्ष्म परीक्षण कर 3 से 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाई जाए।

एक्सपर्ट व्यू

यदि जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो न केवल अपात्र तरीके से नियुक्त हुए कर्मचारियों पर गाज गिरेगी, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल बैंक अधिकारियों और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों पर भी बड़ी विभागीय कार्रवाई हो सकती है।

111 कर्मचारियों का स्थाईकरण

सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी के सदस्य सचिव द्वारा 72 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अस्थाई कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक बनाने की अनुशंसा की गई । इसी तरह पूर्व में सहायक व्यवस्थापक पद पर चयनित 39 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों को मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक बनाने की अनुशंसा भी की गई है । इस प्रकार जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटी ने वर्ष 2022 में कुल 111 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यवस्थापक पद पर स्थाई किया ।

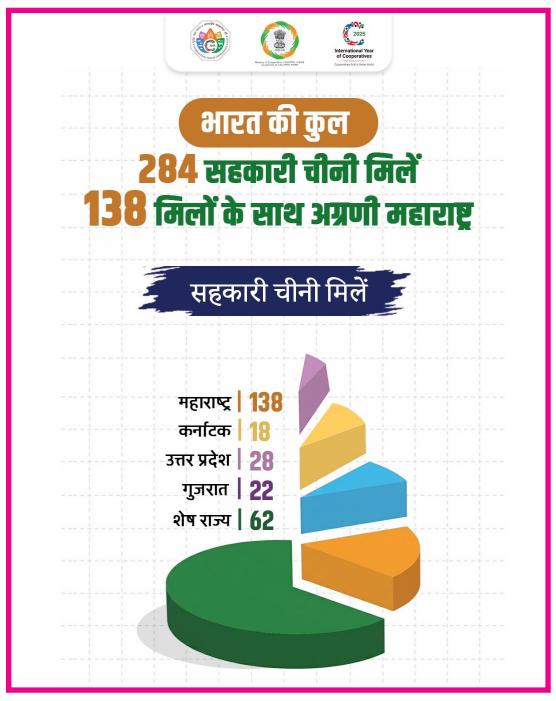

प्रदेश में गेहूँ खरीद हेतु 25 जून तक ज़ारी रहेगी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

'गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल' के माध्यम से किसान गेहूँ विक्रय हेतु 1 फ़रवरी से करवा सकेंगे ऑनलाइन पंजीकरण

जयपुर,। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 हेतु गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य पच्चीस सौ पचासी रूपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। राज्य के किसान अपनी उपज (गेहूँ) विक्रय हेतु पंजीयन 1 फरवरी 25 जून 2026 तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध 'गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। पंजीयन हेतु किसान के पास अद्यतन जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान को जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना है उस बैंक खाते को अपने जन आधार में जुड़वाना आवश्यक होगा। पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर राजकीय कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारियों को एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर समय-समय पर अवगत कराया जायेगा। राज्य में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून, 2026 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। गेहूँ खरीद कार्य हेतु राज्य में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। किसानों से गेहूँ खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जायेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26

सहकारी संस्थाएं बन रहीं ग्रामीण भारत की नई ताकत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली । सहकारी संस्थाएं अब सिर्फ कर्ज देने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि वह ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली नई ताकत बनकर उभर रही हैं। खासतौर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) अब गांवों में रोजगार, सेवाओं और डिजिटल सुविधाओं के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में यह जानकारी दी गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि नए मॉडल बायलॉज के लागू होने के बाद पैक्सको अब 25 से अधिक कारोबार करने की अनुमति मिल गई है। इनमें बीज, खाद और कृषि इनपुट की आपूर्ति, अनाज भंडारण और प्रसंस्करण, पेट्रोल पंप, जनऔषधि केंद्र, पीडीएस की दुकानें और सीएससी खोलना, सरकारी योजनाओं और सेवाओं की डिलीवरी करना शामिल है। इससे पैक्सअब गांवों में बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्र के रूप में काम कर रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण किया गया है जिससे पैक्स ने पारदर्शिता और भरोसे की नई पहचान बनाई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने 67,930 पैक्स के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी जिसके लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की गई। इसके तहत 54,150 पैक्सईआरपी सॉफ्टवेयर से जुड़ चुकी हैं, जबकि 43,658 पैक्सपूरी तरह डिजिटल रूप से लाइव हो चुके हैं। सहकारी क्षेत्र का डिजिटलीकरण होने से लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ी है और युवाओं का भरोसा सहकारी संस्थाओं पर मजबूत हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पंचायत में कम से कम एक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था हो। इस दिशा में मार्च 2025 तक 18,183 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के नए अवसर बन रहे हैं। अनाज भंडारण में पैक्सकी अहम भूमिका को आर्थिक सर्वेक्षण में रेखांकित करने हुए बताया गया है कि 500 नए गोदामों का निर्माण कार्य चल रहा है। इससे किसानों को फसल के बाद नुकसान से राहत मिलेगी और उन्हें सही समय पर बेहतर दाम मिल सकेंगे।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने 67,930 पैक्स के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दी जिसके लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता मंजूर की गई

युवाओं के लिए नई संभावनाएं

सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। साथ ही, शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को सहकारिता से जोड़ा जा रहा है, ताकि वे सहकारी नेतृत्व संभालें, पेशेवर प्रबंधन लाएं और गांवों में उद्यमिता को बढ़ावा दें। यदि बेहतर शासन और पेशेवर प्रबंधन जारी रहा, तो सहकारिता ग्रामीण भारत और युवाओं के भविष्य की मजबूत नींव बन सकती है।

मिनी सहकारी बैंकों का 'निरीक्षण-व्रत'

प्रदेश में 'सहकार से समृद्धि' वाले सहकारिता विभाग के आंकड़ों की जादूगरी देखिए 'प्रदेश की 8160 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 3696 मिनी बैंक चल रहे हैं, लेकिन दो सालों में केवल 90 मिनी सहकारी बैंकों का ही निरीक्षण केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों ने किया है यानी 95 प्रतिशत से ज्यादा मिनी सहकारी बैंकों का निरीक्षण नहीं कर मानो विभाग ने 'भरोसे' की एक नई परिभाषा लिखी है- निरीक्षण मत करो, भरोसा अपने आप बढ़ जाएगा! शायद विभाग का मानना है कि 'निरीक्षण' करने से अधिकारियों की सेहत खराब हो सकती है या फिर उन्हें अपने मातहतों की ईमानदारी पर अटूट विश्वास है। विधायक श्रीमती गीता बरवड़ के सवाल पर सहकारिता विभाग ने विधानसभा में जवाब दिया है कि जिन 90 मिनी सहकारी बैंकों का निरीक्षण हुआ, उनमें एक भी गबन या अनियमितता नहीं मिली। विभाग ने यह भी कह दिया कि अगर कहीं गबन पकड़ा गया, तो अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में विधायक श्रीमती गीता बरवड़ के सवाल का विभाग द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब पढ़कर मानो ऐसा लगा कि विभाग 'मौन व्रत' पर है। अजमेर, जयपुर, अलवर जैसे बड़े केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों ने तो कसम खा रखी है कि वे पिछले दो साल में एक भी मिनी बैंक की दहलीज नहीं लांघेंगे। शायद इनको डर है कि कहीं फील्ड में जाने से उनके सफेद कॉलर पर धूल न लग जाए! पूरे राजस्थान में केवल चूरू केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक थोड़े सक्रिय दिखे, जिन्होंने 29 मिनी सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया। बाकी 17 केंद्रीय सहकारी बैंकों के अधीन संचालित मिनी सहकारी बैंकों में तो निरीक्षण का खाता भी नहीं खुला। जबकि जैसलमेर और जोधपुर सीसीबी के प्रबंध निदेशक सबसे ज्यादा सुकून में हैं। वहां एक भी ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा मिनी सहकारी बैंक का संचालन नहीं किया जा रहा है। न बैंक होगा, न निरीक्षण की टेंशन होगी। ऐसे में पिछले दो सालों में महज 90 मिनी सहकारी बैंकों का निरीक्षण कर, वहां कोई गबन प्रकरण उजागर नहीं होने की बात से खुश होकर विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाकी 3600 मिनी सहकारी बैंकों में सब 'चंगा' है या वहां भी निरीक्षण के लिए किसी 'बड़े कांड' का इंतजार किया जा रहा है?

उम्मीदः 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है कृषि क्रेडिट लक्ष्य

सिर्फ उत्पादन नहीं, उत्पादकता में है गांव और किसान की समृद्धि

अहम संकेत कृषि ऋण लक्ष्य को लेकर है। चालू वित्त वर्ष में 32.5 लाख करोड़ रुपये के कृषि क्रेडिट लक्ष्य को अगले बजट में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर लगभग 36 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है। इस ऋण का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आर्ट-टर्म फसल ऋण होता है । जो किसानों को सात प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है। समय पर भुगतान पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट से यह ऋण और रास्ता हो जाता है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, बीज, उर्वरक और उपकरणों में निवेश का अवसर मिलेगा और ग्रामीण बाजार में माग मजबूत होगी।

-अरविंद शर्मा ।

भारत की खेती केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे और राष्ट्रीय विकास की बुनियाद है। खेत मजबूत होंगे, तभी गांव संघलेंगे व सशक्त होंगे और देश की अर्थव्यवस्था टिकाऊ बन पाएगी। देश की लगभग दो-तिहाई आबादी आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। लेकिन यहां इनोवेशन की गति कम है। वस्तुतः गांव और किसान की खुशहाली जितना बजट पर निर्भर है उतना ही किसानों की मनोदशा पर भी। खेती को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर ही स्थिति तेजी से बदल सकती है, यह किसानों को समझना होगा और केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के जरिये इसे बढ़ावा देना होगा। खेती की सबसे बड़ी कमजोरी कम उत्पादकता दर है और इस दिशा में सरकारों की ओर से बहुत कम काम हो रहे हैं। कुल उत्पादन बड़ने के बावजूद उत्पादकता में भारत आज भी चीन, इजरायल, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों से काफी पीछे है। औसतन दो से ढाई गुना कम उत्पादकता है। गेहूं, धान, दाल और तिलहन की उपज वैश्विक औसत से कम है। लगभग 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास सीमित जमीन है। ऐसे में किसानें की आय बढ़ाने का रास्ता सिर्फ दो हैं, पहला प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना और दूसरा उपज की बेहतर कीमत सुनिश्चित करना। लेकिन वैनें मौर्यो पर प्रगति सैमित है। उत्पादकता बढ़ने पर ही किसान अपनी जमीन पर पारंपरिक उपज की बजाय

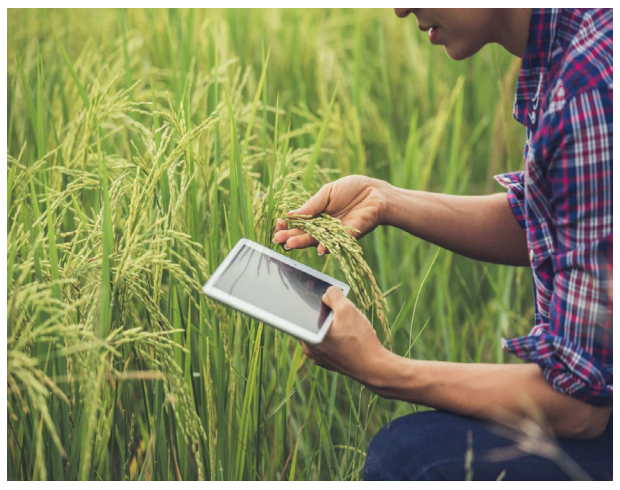

बाजार की मांग के अनुसार फसल बोएंगे। विविधीकरण के लिए सरकार रकार कृषि विधेयक लेकर आई थी लेकिन वह राजनीति की भेंट चढ़ गया। ऐसे में विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। एमएसपी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य डा. बिनोद आनंद का कहना है कि गांवों की समृद्धि के लिए किसानों को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है। फसलों की मार्केटिंग नीति में बदलाव हो। को-आपरेटिव एक्सपोर्ट व कमोडिटी जोन बनाए जाने चाहिए, ताकि फसलों की खरीद, निर्यात और वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया आसान हो सके। खाद्यान्न उत्पादन और निर्यात बढ़ा है, लेकिन उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। खेती की लागत और बिक्री खर्च लगतार बढ़ रहे हैं। सहकारिता से किसानों को उपज की वाजिब कीमत मिल सकेगी प्री-बजट सलाहों-सुझावों से संकेत मिलता है कि सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में कृषि क्षेत्र के लिए बड़े स्तर पर संसाधन बढ़ाने की दिशा में जा सकती है, ताकि उत्पादन, आय और ग्रामीण मांग को गति मिले। अहम संकेत कृषि ऋण लक्ष्य को लेकर है। चालू वित्त वर्ष में 32.5 लाख करोड़ रुपये के कृषि क्रेडिट लक्ष्य को अगले बजट में 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर लगभग 36 लाख करोड़ रुपये किया जा सकता है। इस ऋण का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा आर्ट-टर्म फसल ऋण होता है । जो किसानों को सात प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है। समय पर भुगतान पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट से यह ऋण और रास्ता हो जाता है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, बीज, उर्वरक और उपकरणों में निवेश का अवसर मिलेगा और ग्रामीण बाजार में माग मजबूत होगी। मनरेगा के स्थान पर लाए गए नए कानून जी-रामजी के तहत सरकार ने पहले ही 1.51 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का संकेत दिया है, जो पिछले वर्ष से करीब 70 प्रतिशत अधिक है। पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत सालना छह हजार रुपये की सहायता से मदद जरूर मिल रही है। लेकिन वक्त की मांग है कि किसानने को अपनी आय इतनी बड़े कि उन्हें इसकी जरूरत ही न रहे। यह काम बाजार की मांग के अनुसार वैज्ञानिक खेती से ही संभव है। चजट में अब किसी सब्सि हो की बजाय सीधे तौर पर आकर्षक प्रोत्साहन की जरूरत है। एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डा. कल्याण गोस्वामी भी मानते हैं कि किसान कल्याण के लिए उत्पादन सब्सिडी से आगे बढ़कर गुणवता, निर्यात और तकनीक के एकीकरण पर ध्यान देना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्थ की कमजोरी खेती तक सीमित नहीं है। कृषि रोजगार घट रहा है, लेकिन गैर-कृषि रोजगार उस रफ्तार से नहीं बढ़ा। लिहाजा बजट का ध्यान खेत के आसपास ही ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने पर भी होना चाहिए। पिछले बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वाकांक्षी मिशनों की घोषणा की गई थी। इनमें प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, उन्नत बीज मिशन, दाल आत्मनिर्भरता मिशन और फल-सब्जी उत्पादन को समर्थन देने वाली योजनाएं प्रमुख थीं। इनका उद्देश्य कम उत्पादकता वाले जिलो में खेती को लाभकारी बनाना, बेहतर बीज और अनुसंधान के जरिए पैदावार बढ़ना तथा किसानी की आय में सुधार लाना था। अभी काम जारी है। धन-धान्य येजन के लिए सौ पिछड़े जिलों की पहचान कर ली गई है और आगे की प्रक्रिया चल रही है।

पैक्स स्तर पर तैयार हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण तंत्र

सहकारिता क्षेत्र में भारत एक नई वैश्विक मिसाल कायम करने जा रहा है, जहाँ सहकारिता मंत्रालय की 'सहकार से समृद्धि' पहल के तहत दुनिया की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना अब धरातल पर आकार लेने लगी है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को केवल ऋण देने वाली संस्थाओं तक सीमित न रखकर उन्हें आधुनिक 'एग्री-हब' के रूप में विकसित करना है। सरकार ने पैक्स स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट बनाने की मंजूरी दी है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता विभिन्न सरकारी योजनाओं का अभिसरण है। यह महायोजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और प्रधान मंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम जैसी प्रमुख योजनाओं के मेल से चलाई जा रही है। इस बुनियादी ढांचे के विकास से किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा, जिससे न केवल अनाज की बर्बादी रुकेगी बल्कि परिवहन पर होने वाला भारी खर्च भी कम होगा। अब किसान फसल कटते ही उसे कम दामों पर बेचने को मजबूर नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय पैक्स गोदामों में अपनी उपज सुरक्षित रखकर सही दाम मिलने पर बाजार में बेच सकेंगे। योजना की प्रगति की बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 11 राज्यों की 11 पैक्स में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब 'एक्सटेंडेड पायलट' के

तहत देश भर में 500 से अधिक पैक्स की पहचान की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, 134 पैक्स में निर्माण शुरू हो चुका है जिनमें से 85 में कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो गया है। इस दौड़ में राजस्थान सबसे आगे निकल गया है, जहाँ देश भर में तैयार कुल 85 गोदामों में से अकेले 70 राजस्थान में और 15 महाराष्ट्र में निर्मित हुए हैं। इन गोदामों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य विभाग, नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों ने 220 पैक्स गोदामों को किराए पर लेने का भरोसा दिया है, जिससे पैक्स आत्मनिर्भर बनेंगे और ग्रामीण भारत में खाद्य सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखा जाएगा।

(यह आलेख सहकारी प्रबंध संस्थान जयपुर का है)

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

करोला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. करोला

गेनाराम प्रशासक

हरचंद देवासी व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

किसानों से अपील अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें । पशुपालक, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सीसीबी प्रबंध निदेशक परेश पंड्या गणतंत्र दिवस पर सम्मानित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बांसवाड़ा । जिले में गणतंत्र दिवस 2026 के भव्य समारोह के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में बांसवाड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक परेश पंड्या को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 'प्रशस्ति-पत्र' देकर सम्मानित किया गया। दरअसल बांसवाड़ा जिले में किसानों को समय पर अल्पकालीन फसली ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका एवं पी.एम. श्री किसान योजना से किसानों को लाभान्वित करने के लिए परेश पंड्या को सम्मानित किया गया है । इसके लिए जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव द्वारा प्रबंध निदेशक को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान किया गया है ।

सहकार संगम- 2026 कार्यक्रम का आयोजन

निरीक्षक सहकारी समितियों के संरक्षक और मार्गदर्शक की निभाएं भूमिका - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को-ऑपरेटिव सबोर्डिनेट सर्विसेज (ARCSS) द्वारा 'सहकार संगम-2026' कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसके मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक रहें । उन्होने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि निरीक्षक सहकारिता विभाग की रीढ़ हैं, वे अपनी भूमिका को और विस्तार देते हुए सहकारी समितियों के संरक्षक और मार्गदर्शक बनें। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सहकारी समितियों को वर्तमान समय के अनुरूप सशक्त, सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि आर्थिक युग का प्रभाव विगत वर्षों में सहकारी संस्थाओं पर पड़ा, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना के अनुरूप एवं केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सहकारी सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ऐसे में हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सहकारी समितियों को आर्थिक सशक्त और लाभांश देने लायक बनाएं। श्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं की रोकथाम के लिए सहकारी निरीक्षक निरन्तर सजग रहते हुए प्रभावी मॉनिटरिंग करें। इस दौरान सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारीगण, सहकार भारती के पदाधिकारी एवं प्रदेशभर से सहकारी अधिकारी व निरीक्षक कार्यक्रम में मौजूद रहे।

सहकारिता को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं सहकारी निरीक्षक

कार्यक्रम में एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को-ऑपरेटिव सबोर्डिनेट सर्विसेज की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा चौधरी ने कहा कि राज्य में 600 से अधिक सहकारी निरीक्षक अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारिता को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकार संगम कार्यक्रम इस वृहद् परिवार के लिए संवाद का एक मंच है, जिसके माध्यम से वे अपनी आपसी समझ को बढ़ाते हुए और एक-दूसरे के अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे।

निरीक्षकों को सहकार रत्न पुरस्कार प्रदान किए

सहकारिता मंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन कर 'सहकार संगम-2026' कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। उन्होंने राजकीय सेवा से इतर सामाजिक सरोकार निभाने वाले निरीक्षकों को सहकार रत्न पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही, संगठन की त्रैमासिक पत्रिका सहकार स्तंभ के कवर पेज का विमोचन किया। कार्यक्रम में अधिकारियों-निरीक्षकों एवं उनके परिवारजनों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान बॉलीवुड सिंगर रवीन्द्र उपाध्याय ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधा।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पांचला बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पांचला

गेनाराम प्रशासक

छेन्दाराम व्यवस्थापक

पूर्णतः कंप्यूटरीकृत एवं सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित व किसानों, ग्रामीणों एवं सहकारिता को समर्पित एक प्रगतिशील सहकारी सोसाइटी

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

किसानों से अपील अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें । पशुपालक, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/-☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

देश में इस बार मानसून को कमजोर कर सकता है अलनीनो

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

अलनीनो की स्थिति बनने पर आमतौर पर वर्षा कम होती है और बढ़ जाती है गर्मी

फरवरी के अंत तक हालात सामान्य हो सकते हैं और मार्च से मई तक बनी रह सकती यही स्थिति

अरविंद शर्मा । नई दिल्लीः देश में इस बार मानसून को लेकर चिंताजनक संकेत सामने आ रहे हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, जून के मध्य या इसके बाद प्रशांत महासागर में अलनीनो सक्रिय हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत में मानसूनी वर्षा पर पड़ने की आशंका है। अलनीनो की स्थिति बनने पर आमतौर पर देश में वर्षा कम होती है और गर्मी बढ़ जाती है। आस्ट्रेलिया के मौसम विभाग (ब्यूरो आफ मेट्रोलाजी) के अनुसार, फिलहाल प्रशांत महासागर में ला-नीना की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। प्रशांत महासागर की सतह के नीचे गर्म पानी जमा हो रहा है जो आने वाले महीनों में अलनीनो को जन्म दे सकता है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि फरवरी के अंत तक हालात सामान्य यानी न्यूट्रल हो सकते हैं और मार्च से मई तक यही स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन इसके बाद जून से धीरे-धीरे अलनीनो के सक्रिय होने के आसार बढ़ जाएंगे। आमतौर पर लानीना के बाद आने वाला अलनीनो ज्यादा प्रभावी माना जाता है और यही स्थिति इस साल देखने को मिल सकती है। अलनीनो तब बनता है, जब प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है। इससे हवाओं की दिशा और गति बदल जाती है और इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत में इसका सबसे बड़ा प्रभाव दक्षिण-पश्चिम मानसून पर होता है। अलनीनो के दौरान हवा की दिशा बदल जाती है, जिससे बारिश कम होती है और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। पिछले अनुभव भी इस खतरे की ओर इशारा करते हैं। 1986 में अलनीनो से देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा था। इसी तरह 2014 में मानसूनी वर्षा सामान्य से करीब 12 प्रतिशत कम रही थी। तीन साल पहले 2023 का अलनीनो भी भारत में खेती के लिए परेशानी का कारण बना था। इस बार भी मौसम विज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जून के बाद अलनीनो का असर बढ़ा तो मानसून की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। स्काइमेट के अध्यक्ष जेपी शर्मा का मानना है कि इस बार अलनीनो धीरे-धीरे विकसित होगा। ऐसे मामलों में मानसून पर असर ज्यादा जटिल और कभी-कभी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि, मौसम विभाग यह भी साफ कर रहा है कि अभी यह शुरुआती अनुमान है। जनवरी-फरवरी के आकलन को पूरी तरह सटीक नहीं माना जाता है। मानसून को लेकर ज्यादा भरोसेमंद आकलन मार्च में सामने आएगा, जब समुद्र की सतह के तापमान और हवाओं के रुझान और स्पष्ट होंगे।

16वें वेतन समझौते का सहकारी बैंकों के कार्मिकों को नहीं मिला लाभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

लेकिन श्रीगंगानगर सीसीबी और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में इन आदेशों की पालना नहीं हुई है

जयपुर । राज्य में सहकारी बैंकों के कार्मिकों का बिना किसी कारण 16वें वेतन समझौते का लाभ रोका जा रहा हैं, जिससे सहकारी बैंकों के कार्मिकों को भारी नुकसान हो रहा है । इस स्थिती को लेकर अखिल राजस्थान सहकारी बैंक्स अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रघुवीरप्रसाद शर्मा ने सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग शासन सचिव एवं पंजीयक को पत्र लिखा है । जिसके अनुसार सहकारी बैंक कार्मिकों की नियमित वार्षिक वेतन वृद्धियों में से एक इंक्रीमेंट विलोपति हो जाने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करवाई गई । जबकि एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि न्यायालय के अंतिम निर्णय तक किसी प्रकार की वसूली नहीं होनी है और रिकवरी पर किसी प्रकार स्थगन नहीं है । हालांकि राजस्थान उच्च न्यायलय में लंबित प्रकरणों के क्रम में याचिकाकर्ता को 16वें वेतन समझौते का लाभ देने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा वित्त विभाग की सुस्पष्ट टिप्पणी के साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक एवं समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को एक आदेश भेजा गया । लेकिन श्रीगंगानगर सीसीबी और राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में इन आदेशों की पालना नहीं हुई है ।

गोमी सहकारी समिति की कार्यकारिणी का हुआ गठन

जालोर । जिले के चितलवाना उपखंड क्षेत्र के गोमी गांव में नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया । इस बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के लिए सहकारिता विभाग पंजीयक ने 10 नवबंर 2025 को स्वीकृति आदेश जारी किया । जिसके क्रम में आज नवीन संचालक मण्डल कार्यकारिणी का गठन ब्लॉक सहकारिता निरीक्षक गेनाराम की मौजूदगी में किया गया जिसमें अध्यक्ष पद पर श्रीमती पिंकी देवी पुरोहित, उपाध्यक्ष पद पर अमरदान चारण एवं संचालक सदस्य के तौर पर छतरदान चारण, कैलाशदान चारण, हनुमानाराम विश्नोई, राणाराम प्रजापत, भंवर कंवर, गजेन्द्रसिंह, पताराम मेघवाल, रायेंगाराम चौधरी चुने गए । इस दौरान सीसीबी ऋण पर्यवेक्षक लक्ष्मणराम पुरोहित, शिवपुरा सहकारी समिति व्यवस्थापक करनाराम विश्नोई सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहें ।

गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं

रामदेव क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड सांचौर

पंचायत समिति-सांचौर, जिला-जालोर

किसानों के लिए उन्नत बीज, खाद, यूरिया एवं डीएपी उर्वरक 24 घंटे उपलब्ध हैं

चंदनसिंह विरोल
चेयरमैन केवीएसएस

गेनाराम (Rcs)
मुख्य व्यवस्थापक

किसानों व सदस्यों से अपील : अपनी कृषि जिंसो का को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के माध्यम से ही बेचान करें ।

उपाध्यक्ष - गुमानाराम विश्नोई, संचालक मंडल सदस्य - अमलूराम, दिनेश कुमार, पीराराम, भवानी सिंह, सुनील कुमार, पवनदेवी, पालूदेवी, भजनलाल, भूरी देवी व अजय सिंह

गणतंत्र दिवस पर सीसीबी प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई को किया सम्मानित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जिले में स्थित आदर्श स्टेडियम में आज गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया । इस समारोह में केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर के प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है । दरअसल बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक अनिल विश्नोई को उनके पदीय कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करने के क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई एवं जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया । गौरतलब हैं कि सहकारिता विभाग ने एक माह पूर्व अनिल विश्नोई को बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था । इसके पश्चात सहकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचाने और सीसीबी के अवधिपार और एनपीए ऋणों की वसूली के लिए शाखावार बैंकिंग प्रभारी नियुक्त किए है । हालांकि राज्य सहकारिता सेवा के संयुक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी अनिल विश्नोई के पास वर्तमान में जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक पद का दायित्व भी है ।

पेशुआ में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन: अरविन्ददान चारण निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सिरोही । सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के पेशुआ गांव में नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया। साथ ही संचालक मंडल कार्यकारिणी की निर्वाचन प्रक्रिया सहकारिता निरीक्षक सुरेश कुमार सारस्वत की देखरेख और सभापति राजेश कुमार चारण के सानिध्य में संपन्न हुई। इस निर्वाचन प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सहमति का परिचय देते हुए पेशुआ और फुलेरा के किसानों ने कार्यकारिणी का चयन निर्विरोध किया। इसमें अध्यक्ष पद पर अरविन्ददान चारण, उपाध्यक्ष पद पर रणछोड़लाल रावल सहित संचालक मंडल कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर अशोक कुमार रावल, शंकरलाल मेघवाल, ताराराम सैन, अशोक कुमार चारण, सवाराम कलबी, लालाराम भील, राधेश्याम आढा, लालूदान चारण, नर्मदादेवी रावल एवं लसीदेवी भील आदि चुने गए । इस दौरान कोदरला सहकारी समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार चारण, कोदरला व्यवस्थापक रूपेश कुमार, रोहिड़ा समिति व्यवस्थापक नरेन्द्रदान चारण, सहायक व्यवस्थापक देवेन्द्र कुमार, महेंद्र कुमार, कनकदान, बलवंत दान, भेराराम कलबी, आनंददान और राजपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कृषक उपस्थित रहे।

ग्रामीणों ने जताया उत्साह

नई समिति के गठन और पदाधिकारियों के निर्वाचन के बाद ग्रामीणों में भारी उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से स्वागत किया। किसानों का मानना है कि इस नई समिति के बनने से क्षेत्र में खाद, बीज और कृषि ऋण संबंधी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सकेगा। गौरतलब है कि सहकारिता विभाग पंजीयक ने 14 अक्टूबर को पेशुआ गांव में इस नवीन बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की स्वीकृति जारी की थी ।

सहकारिता मंत्री के आश्वासन के बाद पैक्स कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन काफी आशान्वित

सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी : 11 फरवरी को बजट में मिल सकती है 'वेतनमान' की सौगात

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को पुष्पगुच्छ भेंट करते हनुमानसिंह राजावत

जयपुर, । राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे संघर्ष और एकजुटता का सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिल सकता है। आज जयपुर में राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक से मुलाकात कर, कॉमन कैडर और कर्मचारियों के स्थाई वेतनमान से संबंधित मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान सहकारिता मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राजस्थान सरकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 27 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र और 11 फरवरी को पेश होने वाले राज्य बजट में कर्मचारियों के वेतनमान की समस्या के स्थाई समाधान हेतु प्रावधान करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी आवश्यक कार्यवाही के लिए कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान हनुमान सिंह राजावत, मदन मेनारिया, देवेन्द्र कुमार सेदावत, खेतपाल सिंह बालोत और नरपत खां शेख (जालोर) आदि उपस्थित रहे।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों की नजरें अब 11 फरवरी के बजट पर टिकी हैं, पैक्स व्यवस्थापकों के लिए एक ऐतिहासिक बजट के रूप में देख रहे हैं

विभागीय स्तर पर कार्यवाही तेज

सहकारिता मंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खंडेलवाल से भी मुलाकात की। तो अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने विभाग द्वारा कॉमन कैडर और वेतनमान को लेकर की जा रही प्रगति से अवगत कराया, जिससे कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगी है।

एकजुटता की जीत : हनुमान सिंह राजावत

राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष हनुमान सिंह राजावत ने कहा, यह प्रदेश के ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सफल कार्य बहिष्कार और अभूतपूर्व एकजुटता का ही परिणाम है कि सरकार और विभाग आज पैक्स कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) रविवार, 1 फरवरी 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक 142.65 करोड़ रुपए किए वितरित

नाबार्ड ने राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को जारी किया 14 हजार करोड़ का पुनर्वित्त, 3 सीसीबी में गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) को भारी मात्रा में पुनर्वित्त सहायता प्रदान की है। साथ ही आरएससीबी द्वारा तीन केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) में गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति भी की गई है । दरअसल राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत यह जानकारी उपलब्ध करवाई है । नाबार्ड ने आरटीआई में राजस्थान के सहकारी बैंकिंग और ऋण वितरण से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। जिसके अनुसार राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (आरएससीबी) को 16 जनवरी 2026 तक करीब 14 हजार करोड़ का पुनर्वित जारी किया गया है । इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 8670 करोड़ 92 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 6264 करोड़ 22 लाख का पुनर्वित जारी किया है । वही नाबार्ड ने आरटीआई में गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति को भी स्पष्ट किया है । नाबार्ड के मुताबिक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा भरतपुर, जैसलमेर एवं पाली सीसीबी में गार्जियन ऑफिसर नियुक्त किए गए है । जबकि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के पास गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

142.65 करोड़ का ब्याज अनुदान वितरित किया

नाबार्ड ने आरटीआई के तहत जानकारी देते हुए बताया है कि अल्पावधि फसल ऋणों की वसूली के लिए भारत सरकार द्वारा देय 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के तहत अब तक कुल 142.65 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। नाबार्ड के अनुसार, वह किसानों को 3 प्रतिशत 'शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन' (पीआरआई) योजना के कार्यान्वयन में एक पासिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार से प्राप्त रिलीज आदेशों के आधार पर नाबार्ड यह ब्याज अनुदान राशि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक को जारी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक इस योजना के तहत कुल 142.65 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान वितरित किया जा चुका है।

कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली

नाबार्ड से आरटीआई का जवाब मिलने के बाद गार्जियन ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर, जब राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से दूरभाष के जरिए संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली पाई है !

डीआरए के तहत सहकारी बैंकों को दिया 300 करोड़ का ऋण

नाबार्ड द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता (डीआरए) के तहत ऋण जारी किया जाता है । जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5 केंद्रीय सहकारी बैंकों को करीब 150 करोड़ का ऋण दिया गया । इनमें सीकर सीसीबी को सर्वाधिक 75 करोड़ एवं गंगानगर सीसीबी को 35 करोड़, कोटा सीसीबी को 15, चूरू सीसीबी को 15 करोड़ तथा सिरोही सीसीबी को 10 करोड़ का ऋण दिया गया । इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2 केंद्रीय सहकारी बैंकों को 153 करोड़ का ऋण दिया गया । इनमें गंगानगर सीसीबी को 103 करोड़ एवं झुंझुन सीसीबी को 50 करोड़ का ऋण डीआरए के तहत दिया गया है ।

जहाजपुर क्षेत्र की समस्त सहकारी समितियों के पास स्वयं के गोदाम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । विधानसभा में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार ने कहा कि जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 58 ग्राम सेवा सहकारी समितियां (38 जहाजपुर एवं 20 कोटड़ी) पंजीकृत हैं। इनमें ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कुल 78 भवन एवं गोदाम हैं, जिनमें से 70 भवन एवं गोदाम उपयोगी हैं। सहकारिता मंत्रीप्रश्नकाल के दौरान सदस्य श्री गोपीचन्द मीणा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की कोटड़ी सहित अन्य सहकारी समिति द्वारा किसानों के मुआवजे की राशि संबंधी विषय पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। इससे पहले विधायक मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री कुमार ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर में कोटड़ी तथा जहाजपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति तथा 58 ग्राम सेवा सहकारी समितयां पंजीकृत है। इन सभी पंजीकृत सहकारी समितियों के पास स्वयं के भवन/गोदाम हैं। श्री कुमार ने बताया कि समितियों के पास नियमानुसार वैध स्वामित्व वाली भूमि की उपलब्धता होने एवं नियमानुसार संबंधित प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक/उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है।

पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना का ऑनलाइन कार्य भी 60 फीसदी से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ठप्प पड़ा है

ब्याज अनुदान की राशि आवंटन नहीं होने के मामले में सीसीबी प्रशासक को सौंपा ज्ञापन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर । जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को पिछले दो साल से ब्याज अनुदान की राशि का आवंटन नहीं हुआ है । इस कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने और संस्थापन व्यय से लेकर ऑडिट फीस चुकाने तक के लाले पड़े हुए है । यहां तक कि केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना का ऑनलाइन कार्य भी 60 फीसदी से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ठप्प पड़ गया है । अब इस समस्या के निराकरण के लिए जोधपुर सहकारी पैक्स कर्मचारी यूनियन ने जिला अध्यक्ष विरेन्द्रसिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर एवं जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा हैं । जिसमें बताया गया है कि जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, खाद-बीज वितरण और राशन वितरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। फिर भी उन्हें समयबद्धता से ब्याज अनुदान का भुगतान नहीं किया जा रहा है । इस दौरान यूनियन के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश बिश्नोई, कानाराम पटेल, संरक्षक मंगलाराम चौधरी, मेघाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष प्रेमाराम चौधरी, मीडिया प्रभारी प्रभु राम चौधरी, मूल सिंह राठौड़, भंवर सिंह राठौड़, सुरेश कुमार बाता, पूर्ण प्रकाश शर्मा, विशन सिंह इंदा, दिलीप सिंह जोधा सहित कार्यकारिणी के सदस्य और जिलेभर के व्यवस्थापक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

ज्ञापन में उठाई गई यह मुख्य मांगें

ज्ञापन में मुख्य रूप से संस्थाओं का ब्याज खाता अलग खोलने, पूर्व में लगाए गए एरियर ब्याज को वापस लौटाने, किसानों की साख सीमा (क्रेडिट लिमिट) बढ़ाने का अधिकार ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देने और योग्यता रखने वाले सहायक व्यवस्थापकों को समितियों का चार्ज सौंपने की मांग की गई है।

जोधपुर सीसीबी को 3 एवं 4 प्रतिशत पेटे 33 करोड़ हो चुकी आवंटित

सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत जोधपुर जिले में 1 लाख 21 हजार किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से रबी व खरीफ सीजन के दौरान 900 करोड़ का फसली सहकारी ऋण मुहैया करवाया जाता है । इस ऋण का समय पर चुकारा करने पर संबंधित केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है । इसके क्रम में दिसंबर 2024 से लेकर अब तक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा जोधपुर केंद्रीय सहकारी बैंक को करीब 33 करोड़ की राशि आवंटित की गई है । इसमें से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे करीब 24 करोड़ की राशि तथा 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे 9 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है ।

81 करोड़ की राशि जारी करवाने की उठाई मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । राज्य सरकार द्वारा कर्ज माफी योजना 2018 एवं 2019 में विलंब भुगतान पर 8 प्रतिशत की दर से केंद्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज देने की घोषणा की गई । इस घोषणा के बाद केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर को करीब 124.30 करोड़ की राशि जारी की जानी थी । लेकिन सरकार स्तर से महज 43.13 करोड़ की राशि जारी की गई । जबकि बकाया 81.17 करोड़ की राशि वर्तमान तक बकाया चल रही है । यहां केंद्रीय सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुपालना में लेखा पुस्तिका में 'राज्य सरकार से प्राप्य' मद में दर्शाई जा रही इस 81.17 करोड़ की राशि का शत-प्रतिशत प्रावधान करना पड़ा । जिससे यह केंद्रीय सहकारी बैंक करीब 32 करोड़ की हानि में चली गई है । इस स्थिती को लेकर ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन यूनिट बाड़मेर ने सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग शासन सचिव एवं पंजीयक को पत्र भेजकर बकाया राशि जल्द जारीकरवानेकीमांगकीगईहै।

कार्मिकों में निराशा और असंतोष व्याप्त

ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन यूनिट बाड़मेर के अध्यक्ष दीपेन्द्रसिंह, सचिव गौरव कुमार पारिक एवं ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भीखाराम विश्नोई एवं सचिव विक्रमसिंह राठौड़ ने बताया कि बैंक की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बैंक कार्मिकों के आर्थिक परिलाभों यथा दीपावली बोनस, उपार्जित अवकाश नकदीकरण एवं भविष्य के वेतन समझौतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एवं कार्मिकों में सेवा सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे कार्मिकों में निराशा एवं असंतोष व्याप्त है।

राशन डीलरों के कमीशन में 10 प्रतिशत वृद्धि की

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशवासियों की खाद्य सुरक्षा के साथ राशन डीलरों की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। राशन डीलर को मिलने वाले कमीशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उन्हें समय पर भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उचित मूल्य दुकानदारों के गत नवंबर तक के कमीशन के भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री ललित मीना द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बारां जिले में 33 उचित मूल्य दुकानों के आवंटन आदेश जारी किये जा चुके है। जिले में 8 दुकाने नवसृजित भी की गयी हैं। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि बारां जिले में वर्तमान में कुल 575 उचित मूल्य की दुकानें हैं। अधिकारियों व प्रवर्तन कार्मिकों द्वारा वर्ष 2020 से 2025 तक बारां में उचित मूल्य् दुकानों के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 434 उचित मूल्ये दुकानों को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किये गये। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 82 उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गये एवं 82 सम्बन्ध (अटैचमेंट) के आदेश जारी किये गये। श्री गोदारा ने कहा कि निलंबित किये गए उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस, दुकानदार द्वारा संतुष्टि पूर्व जवाब देने पर बहाल किये जाते है। उन्होंने बारां जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों और पदस्थापित अधिकारियों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण वितरण की प्रक्रिया फाइनेंशियल इंक्लूजन गेटवे पोर्टल पर इन्टीग्रेशन का कार्य प्रक्रियाधीन

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में महज 52 हजार गोपालकों को ही वितरित हुआ ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान में 'गोपालकों' के अच्छे दिन आए या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में सहकारी बैंक जरूर 'पहलवान' नजर आ रहे हैं। सरकार ने बड़े तामझाम के साथ 2,50,000 गोपालकों को कर्ज बांटने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ताजा रिव्यू रिपोर्ट (15.01.2026) बता रही है कि सिस्टम की गाड़ी 'कछुआ चाल' से भी पीछे चल रही है। योजना को शुरू हुए 1 साल बीत गया, लेकिन इस वित्तीय वर्ष की लक्ष्य प्राप्ति का मीटर 25.20 फीसदी पर आकर ऐसा अटका है जैसे बिना चारे की गाय खूंटे से बंधी हो। लक्ष्य था ढाई लाख का, और बैंक अब तक केवल 52,546 गोपालकों को इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवा पाई हैं । बाकी के पौने दो लाख गोपालक शायद अभी भी बैंकों के बाहर 'पधारो म्हारे देश' की धुन पर कागजों का मिलान कर रहे हैं। जबकि राज्य सरकार 11 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है । गौरतलब हैं कि राज्य सरकार ने 2,50,000 गोपालकों को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण बांटने का लक्ष्य भी गत बजट में रखा था ।

टारगेट 'हवा-हवाई', उपलब्धि 'ज़मीन' पर

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केंद्रीय सहकारी बैंक के मार्फत ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा 2,50,000 गोपालकों को ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । लेकिन राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की 15 जनवरी 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट बता रही है कि अभी तक केवल 52,546 गोपालकों को ही पैक्स ऋण उपलब्ध करवा पाई है । जो लक्ष्य का महज 25.20 प्रतिशत ही है ।

चेतावनीः पुराना चुकाओगे, तभी नया पाओगे

रिपोर्ट के अंत में लिखा है कि ऐसे गोपालक जिन्होंने योजना के प्रारम्भ में ऋण लिया था, उनको सहकारी बैंक स्तर से वसूली करते हुए पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। वर्तमान में अल्पकालीन अवधिपार ऋण होने की स्थिति में उसका चुकारा होने पर ही नवीन ऋण दिया जाएगा । जबकि रिपोर्ट के अनुसार गोपाल क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ऋण देने के लिए एफआईजी पोर्टल पर इन्टीग्रेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है । जिससे 15 दिसंबर के बाद से ऋण वितरण की प्रक्रिया ठप्प पड़ी है । हालांकि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत केवल ऋण स्वीकृत किए जा रहें है ।

सिरोही 'टॉप-पर', जैसलमेर में 'मौन व्रत'

रिपोर्ट में सिरोही केंद्रीय सहकारी बैंक 77 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अव्वल हैं। वहीं दूसरी ओर जैसलमेर का खाता ऐसा है जैसे वहां के गोपालकों ने कसम खा ली हो कि "कर्जा लेंगे नहीं और बैंक जाएंगे नहीं।" वहां उपलब्धि का आंकड़ा 0.00 प्रतिशत पर टस से मस नहीं हुआ है। शायद जैसलमेर की फाइलें अभी रेगिस्तान की किसी रेत के टीले के नीचे ठंडी हवा खा रही हैं। ऐसे ही हालत पाली सीसीबी में भी हैं । यहां पूरे जिले में केवल 9 लोगों को ऋण वितरित हुआ। ऐसा लगता है जैसे पैक्स व्यवस्थापक ने खुद घर जाकर उन 9 लोगों की मिन्नतें की होंगी कि "भाई, ले लो वरना रिपोर्ट खाली जाएगी।" अलवर और अजमेर की हालत भी ऐसी है कि वहां की बैंकों में 'गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना' में आंवटित लक्ष्य की फाइलों पर कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।